

भ्रष्ट एसपी के खिलाफ बार की हड्डताल

पलवल (म.पो.) जिला बार एसोसिएशन पलवल और फरीदाबाद दोनों मिलकर 27 अक्टूबर को होने वाली गृहमंत्री अमित शाह की रैली के विरुद्ध काली पट्टी बांधकर उनका विरोध करेगी। विरोध का मूल कारण यहां का एसपी राजेश दुग्गल है। इनकी पल्ली सिरसा से सांसद निर्वाचित हैं। वकीलों का आरोप है कि सांसद पल्ली के बूते एसपी दुग्गल आम जनता तो क्या सीएम और पीएम को भी कुछ नहीं समझते। इसी धौंस में वे पूरी बेशर्मी से खुला खा रहे हैं और नंगा नहा रहे हैं।

पलवल में अवैध वसूली करके अपनी आय से अधिक संपत्ति का भी परिचायक है। इसने जिला पलवल में वकीलों में गुटबंदी करके गोली चलावाने के पूरे इंतजाम कर रखे हैं। इस उच्च अधिकारी पलवल ने आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों को शरण में लेकर उनसे उन्हें सीधे काले धधे और अवैध अपराध कराने का काम किया है। पलवल का यह उच्च अधिकारी पहला ऐसा व्यक्ति है जिसके कार्यकाल में छँगुलिसकर्मियों ने इसकी ओछी विचारधारा की वजह से आत्महत्या की है और उनकी लाशों को बेचकर सम्बन्धित गुनहगारों की जमानत तक करा दी है। समझा जाता है कि उन अपराधियों से या मोटे पैसे तो खाए ही हैं, उनसे आगे और भी अपराध कराए जाने की सम्भावना है। इनके काले कारनामों का विरोध करने वाले वकीलों के खिलाफ भी दुग्गल झूठे मुकदमे दर्ज कराने में नहीं हिचकते। है ऐसे मामलों की एक लम्बी लिस्ट है। इसका ताजा तरीण उदाहरण एफआईआर नंबर 649 हुई है।

जिले के एसपी होने के नाते वे अपने मातहतों के तबादले एवं तैनातियों के अधिकार का खुल कर दुरुपयोग कर रहे हैं, बल्कि यों कहा जाय कि खुल कर बैंच रहे हैं। लगभग हर थाने चौकों के नाके तक पर तैनाती के दाम तय हैं। इनके माध्यम से ही हफ्ता वसूली कराई जाती है, संर्दंवस सुधी पाठक 'मजदूर मोर्चा' उस खबर को याद करें जिसमें गवर्नर फिरोज पुर का एक युवा मोर्चासाइकिल सवार हाइवे पर ट्रैक से कुचल कर भगा था उसकी मौत के पीछे भी असली कारण नाकेबंदी द्वारा ट्रैकों से वसूली था। जातिगत वैमनस्यता को बढ़ावा देने के लिए एसपी/एसटी एक्ट का दुरुपयोग करते हुए बड़ी संख्या में झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं। लोगों में चर्चा के अनुसार यह संख्या 100 के करीब बताई जा रही है।

दुग्गल के उक्त आपराधिक कृत्यों के



राजेश दुग्गल, एसपी पलवल

लूट के साथ-साथ सांसाधनों का दुरुपयोग

महकमे के भीतरी सूत्र बताते हैं कि दुग्गल साहब सरकारी वाहन के जरिये रोजाना गुड़गांव रित्यत अपने साले सुमित जो गुड़गांव नाम निगम में ज्याइट कमिशनर है के यहां दूध भिजवाते हैं, इसी तरह सांसद पल्ली के दिल्ली आवास पर भी दूध की सप्लाई की जाती है। जितने का दूध नहीं उससे कई गुण अधिक उसके भिजवाने पर खर्चा हो जाता है। इसी को तो कहते हैं माल-ए-मुफ्त, दिल-ए-बेरहम। दुग्गल साहब ये फिजल खर्चों के बीच इसलिये कर पा रहे हैं क्योंकि इसका बोझ सीधे सरकार यानी करदाता पर पड़ रहा है।

सूत्र बताते हैं कि दिल्ली, गुड़गांव, हिसार व सिरसा में इन्होंने अपने जौ घर बना रखे हैं उनमें काम करने के लिये भी पलवल से ही विभागीय कर्मचारियों को तैनात कर रखा है। एक और तो संसाधनों की कमी का रोना रोया जाता है। वहीं दूसरी ओर इतनी बेदर्दी के साथ सरकारी सांसाधनों का खुला दुरुपयोग किया जा रहा है। क्या यह सब उच्चाधिकारियों व खट्टर तथा विज को नजर नहीं आता?

महेनजर पलवल बार एसोसिएशन ने सरकार से इनके तबादले की मांग के साथ साथ इन पर लगे आरोपों की जांच की मांग भी की है। जिब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक वकीलों ने हड्डताल पर रहने का निर्णय किया है। इसकी शुरुआत 27 अक्टूबर को अमितशाह की फरीदाबाद में होने वाली के बहिकार से कर दी है। इसके अलावा दुग्गल वह उनकी सांसद पल्ली सुनीता के पुतले फुकने का एलान भी किया गया है।

पलवल में इस अधिकारी की यह दूसरी बार पोस्टिंग है और यह छोटे पुलिस मुलाजिमों

सांप की रस्सी, रस्सी का सांप बना देती है पुलिस रिश्वत मिले तो क्रिमिनल के स नहीं तो सिविल



गंगाराम पूनिया, एसपी करनाल

करनाल (म.पो.) स्थानीय व्यापारी पुलिसेतम बंसल ने सन् 2006 में गांव रायपुर रोड़ (थाना इन्द्री) स्थित 1000 वर्ग गज जमीन का सौदा 29 लाख रुपये में किया था। 11 लाख रुपये देकर बंसल ने प्लॉट पर अपने ताले लगा कर कब्जा ले लिया था। करार के मुताबिक विक्रेता को बैंक का आठ-नौ लाख कर्ज चुका कर बंसल के नाम रजिस्ट्री करा कर शेष 18 लाख बसूलने थे। लेकिन इसके विपरीत विक्रेता ने बैंक का कर्ज लौटाने की बजाय गुंडागर्दी से प्लॉट के ताले तोड़कर, दिया हुआ कब्जा बापस ले लिया।

क्रेता बंसल ने स्थानीय अदालत में 2007 में केस डाला और जीत गये। विक्रेता सेशन कोर्ट में गया और हार गया। इस पर कोर्ट के आदेश पर बंसल ने बैंक का पूरा भुगतान करके शेष रकम विक्रेता को अदा कर दी जिसके बदले 2012 में कोर्ट ने बंसल के नाम रजिस्ट्री करा दी। विक्रेता ने इसके विरुद्ध हाई कोर्ट जाकर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया। करीब साल भर बाद साल भर बाद स्थगन आदेश भी हट गया और बंसल यहां भी 2018 में केस जीत गये।

बंसल कब्जा लेने मौके पर गये तो पाया कि वहां पर काफी भारी-भरकम मरीजें आदि चल रही थीं। विक्रेता ने बंसल के पांच पकड़ कर दो-तीन साल का समय मांगा और तब तक के लिये 40 हजार रुपये किराया देने तय कर लिया और इस बाबत कानूनी दसावेज बनाये गये।

2021 में बंसल को पता चला कि सन् 2015 में क्रेता ने इस प्लॉट के आधे भाग

की जातिगत आधार पर इंकायरी खोल कर उनसे मोटे पैसे वसूल कर इंकायरी बंद करता है। इसकी इलेक्शन कमिशन में बार-बार शिकायत होती है और यह बैंक डेट में मेडिकल बनवाकर छुट्टी पर चला जाता है। जिसमें इसके साथ चंडीगढ़ स्थित उच्च अधिकारी भी

शामिल हैं उसकी जांच भी होनी चाहिए। आमजन के अनुसार इसके पास एक कोटी रुपयोगी और भी अधिक रकम देकर अपना उल्लंघनीय करवा लेती है। वही इस मामले में हुआ भी।

आर्थिक अपराध शाखा ने इस मामले को क्रिमिनल के स नाम कर सिविल बता

दिया। बंसल ने इसकी शिकायत पुनः एसपी पूनिया से की तो उन्होंने केस को रिव्यू करने के लिये नई-नई भर्ती हुई, 2019 बैच की आईपीएस अधिकारी हिमांद्रि कौशिक, एसपी इन्द्री को सौंप दिया। करीब 6-7 महीने बंसल के चक्कर कटवाने के बाद इस नवयुवती पुलिस अधिकारी ने भी आर्थिक अपराध शाखा के इन्स्पेक्टर की कार्रवाई को उचित ठहरा दिया।

इसके बाद बंसल ने कार्यकुशलता एवं ईमानदारी का ढोल पीटने वाले गृहमंत्री अनिल विज को दरखास्त लगाई। काम को लटकाने व भटकाने के लिये विज ने जिला अधिकारियों की एक कमेटी गठित कर दी, यानी भैंस गई पानी में। अब बंसल इस कमेटी के एक सदस्य डीआरओ (जिला राजस्व अधिकारी) के चक्कर कर लगा। यानी मामले को तुर्ज-फुर्ज सुलझा कर निपटाने की बजाय विज साहब ने और भी उलझन की ओर धकेल दिया है। कायदे से तो गृहमंत्री को एसपी पूनिया से जवाब तलब करना चाहिये था कि दिन के उजाले की तरह साफ-साफ दिखाई देने वाला धोखा-धड़ी व जालसज्जी का मामला सिविल के स नाम के बाबत दिया गया ?

अब देखने वाली बात यह है कि एसपी पूनिया अपने महकमे में चल रही इस रिश्वतखोरी को पकड़ पाने के काबिल नहीं हैं अथवा वे खुद इसके संरक्षक एवं हिस्सेदार हैं, इसका फैसला वे खुद ही करें। रही बात नवनियुक्त एसपी हिमांद्रि कौशिक की तो वे क्या सीख रही हैं और कैसी अफसर बनेंगी, यह भी एक गंभीर प्रश्न है।

शिकायत है। दुग्गल साहब जब भी जिले में तैनात होते हैं तो ये साहब खींचने की रफतार इतनी तेज़ कर देते हैं कि किसी भी जिले में दो तीन महीने से ज्यादा नहीं टिक पाते। किसी भी जिले में टिकने का अब तक का सबसे बड़ा रिकार्ड इन्होंने पलवल में ही बनाया है।

सीवर के सड़े पानी में मनाई दीवाली



बिल्कुल बंद है। कोई खास जरूरत पड़ने पर ही लोग आते हैं।

सड़क के किनारे थोड़ा ऊपर से लोग आते हैं वहां भी दीपावली पर दुकानों ने अपनी दुकान सजा दिया। अब लोगों के पास कोई रास्ता नहीं। दो-चार दिन तो लोग परेशानी झेल भी लेंगे किंतु लगातार सीवर की गंदगी में रहने से कुछ लोग तो नहर के बहाव से बच रहे हैं।

भी कहना है कि गंदगी में आने-जाने से भयंकर बीमारी भी हो सकती है। कुछ लोगों का कहना है कि हाल ही में निवार हुई मेयर सुमन बाला ने उन्हें बताया है कि बातौर मेयर उसने तो इस समस्या का समाधान करने के लिये बहुत प्रयास किया था। लेकिन इसके विपरीत स्थानीय विधायक सीमा त्रिखा नहीं चाहती कि यहां के निवासियों को सीवर समस्या से कोई राहत मिल पाये।